(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों ने उक्त उद्योग के विकास के लिये आवश्यक कार्यक्रमों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिये तत्काल कार्यवाही करने के अपने वचन को भी दोहराया था;

(ग) यदि हां, तो अभी तक सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान हेतु क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) खादी ग्रामोद्योग के तहत आगामी तीन वर्षों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम: (क) से (घ) जो विभिन्न निकाय/संस्थान तथा श्रमिक देश मे खादी तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन और विकास में लगे हैं, उनमे प्राप्त सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश के प्रत्येक चुनिन्दा जिलों में लगभग 10,000 व्यक्तियों के लिये रोजगार सृजन करने हेतु एक विशेष रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है। उक्त कार्यक्रम के तहत अब तक 14 जिले शामिल किये गये हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 50 जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में डी.आर.डी.ए. तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

New Power Plant orders

142. SHRI N. E. BALARAM: Will the PRTME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact the , the inflow of new Power Plant orders of the BHEL has been declining over the past few years;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor- and

(c) what steps are being taken to enhance the orders?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAI DEVELOPMENT) WITH ADDITIO NAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) Order; booked by BHEL for power plants wen for total capacities of 2,010 MW in 1990-91, 373 MW in 1991-92 and 1,33C MW in 1992-93. The main reasons for inadequate orders for power plants is the resource constraints faced by custom mere.

(c) Steps taken by BHEL to improve its order book position are as follows:

— Marketing drive to obtain balance orders of VIII Plan for power generation equipment.
— Enhancing business from existing power stations through life extension, renovation/modernisation of old equipment.
— Joint working with reputed companies for formulating bids with consortium arrangements.
— Greater thrust on exports (both physical and deemed) by focusing on specific potential areas.
— Diversification into new growth areas where BHEL's existing infrastructure skills and capabilities would be gainfully utilised.

Arrears due from State. Electricity Board

1473. SHRI N. E. BALARAM:

SHRI GAYA SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether it is a fact that arrears from various State Electricity Boards and Power Corporations to BHEL have increased to about 2000 crores rupees: